Regd. N0. 185

Haryana College Teachers' Association

(Affiliated to AIFUCTO)
website: www.hcta.in

Dr. Narender Chahar
President
Vaish College, Bhiwani
Mob. 098133-26900
Email: narenderchahar11@gmail.com

Dr. S.P. Singh Sidhu
General Secretary
M.M. (P.G.) College, Fatehabad
Mob. 9354825103
Email: dspsidhu@gmail.com

Ref. No. HCTA/08/2018 Date. 28/08/2018.

सेवा में,

माननीय मुख्यमन्त्री
हरियाणा सरकार।
चण्डीगढ़।

विषयः– छठे वेतन आयोग की विसंगतियां दूर करने हेतू।

श्रीमान् जी,

हरियाणा के सभी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में सांतवे वेतन आयोग की सिफारिशों को तुरन्त प्रभाव से लागू करने की घोषणा पर समस्त शिक्षक वर्ग आपका और हरियाणा सरकार का हृदय की गहराईयों से धन्यवाद करता है।

मान्यवर हम आपका ध्यान छठे वेतन आयोग में रह गयी विसंगतियों की ओर दिलाना चाहते हैं जिन्हें दूर करने का वायदा आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र, हरियाणा–2014 में विशेष तौर पर किया था। जिनको दूर किए बिना सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें अपना महत्व खो देती हैं। छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करवाने के लिए हम अनेक बार उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पत्राचार एवं मीटिंग कर चुके हैं। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अधिकारीगण अपनी मनमर्जी से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश को दरकिनार करके बेतुके नियम व शर्तें लागू कर देते हैं। इसलिए अब इन विसंगतियों को आपके संज्ञान में लाना अपना कर्तव्य समझते हैं ताकि एक शिक्षा और शिक्षक हितैशी सरकार, हमारी समस्याओं का समाधान कर सके व अपना चुनावी वायदा भी पूरा कर सके। प्रमुख विसंगतियां इस प्रकार हैं–

1. छठे वेतन आयोग में यू.जी.सी की ओर से बिना NET/SLET/SET केवल Ph.D. या M.Phil के आधार पर नियुक्त सहायक प्रोफेसर को पीएच.डी. की पांच तथा एम.फिल. की 2 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की गई थी ताकि शिक्षक शोध कार्य की ओर भी ध्यान दें। लेकिन हरियाणा सरकार के वित विभाग द्वारा अभी तक इसका लाभ 1 सितम्बर, 2009 के बाद लगे शिक्षकों को नहीं दिया गया हालांकि वित विभाग, हरियाणा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अपने पत्रों कमांक 1/46/2009–4 (PR) (FD) दिनांक 20.08.2017 तथा नं. 1/46/2009–4 (PR) (FD) दिनांक 08.01.2018 (के माध्यम से स्पष्टीकरण मांग चुका है। इनके प्रत्युत्तर में यू.जी.सी. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने पत्रो नं. F.9-3/2010 (PS) Pt.fl. दिनांक 07.11.2017 तथा नं. F.9-3/2010 (PS) Pt.Fl. दिनांक 06.03.2018 (Copy attached) के द्वारा स्पष्ट कर चुका है कि बिना बिना NET/SLET/SET के Ph.D. या M.Phil के आधार पर लगे सहायक प्राध्यापकों को Ph.D. की पांच और एम.फिल. की 2 अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान की जाएं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से दो बार स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद भी वित विभाग, हरियाणा सरकार इसको लागू नहीं कर रहा।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने छठे वेतन आयोग एवं न्यूनतम योग्यता मानदंड के नोटिफिकेशन नं. F.3-1/2009, दिनांक 28.06.2010 को (Copy attached) में बिना NET/SLET/SET के Ph.D. या M.Phil के आधार पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक से वरिष्ठ वेतनमान (Senior Scale Stage I to Stage II, i.e. AGP 6000 to 7000) की प्रमोशन पीएच.डी. को चार वर्ष

Regd. N0. 185

Haryana College Teachers' Association

(Affiliated to AIFUCTO)
website: www.hcta.in

Dr. Narender Chahar
President
Vaish College, Bhiwani
Mob. 098133-26900
Email: narenderchahar11@gmail.com

Dr. S.P. Singh Sidhu
General Secretary
M.M. (P.G.) College, Fatehabad
Mob. 9354825103
Email: dspsidhu@gmail.com

Ref. No.....

Date.....

तथा एम.फिल. को पांच वर्ष उपरान्त देने का प्रावधान है। मान्यवर हरियाणा सरकार का उच्चतर शिक्षा विभाग इसकी पालना नहीं कर रहा। महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ इस विषय में भेदभाव कर रहा है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के विरूद्ध जाकर अपनी मनमर्जी कर रहा है।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने छठे वेतन आयोग के नियमानुसार एम.फिल./पीएच.डी. की जो अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी वो शिक्षक के मूल वेतन में समायोजित होगी। हरियाणा सरकार का उच्चतर शिक्षा विभाग एवं वित विभाग इस विषय में भी अपनी मनमानी कर रहा है और इसका लाभ भी महाविद्यालय के शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा। जबकि उच्चतर शिक्षा विभाग अपने पत्र कमांक 24/242–2013 सी–1 (4) दिनांक 18.06.2015 (copy attached) के द्वारा एम. फिल./पीएच.डी. की अग्रिम वेतन वृद्धि को मूल वेतन में विलय करने बारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्पष्टीकरण मांग चुका है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने पत्र कमांक न. F.11-6/2011 (PS) दिनांक 18.08.2015 (copy attached) के द्वारा स्पष्ट कर चुका है कि अग्रिम वेतन वृद्धियां मूल वेतन में विलय होंगी। लेकिन कई वर्ष बीत जाने पर भी उच्चतर शिक्षा विभाग इसकी अनुपालना नहीं कर रहा । मान्यवर शिक्षक वर्ग जो कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए, समाज के कल्याण के लिए निरन्तर प्रयासरत रहता है, उसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इस प्रकार भटकना पड़े और न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े तो यह कतई शोभनीय नहीं होता है बल्कि शिक्षकों का भी समय एवं धन बर्बाद होता है एवं इन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। इससे बच्चों के भविष्य पर भी प्रभाव पड़ता है। हरियाणा सरकार जो कि उत्कृष्ट शासकीय प्रबंधन के लिए जानी जाती है जो सबका साथ तथा सबका विकास में विश्वास रखती है, वो अपने शिक्षकों के साथ भेदभाव नहीं होने दे सकती।
यहां गौरतलब यह है कि उपरोक्त लाभ हरियाणा के प्रमुख विश्वविद्यालयों में दिए जा रहे हैं। लेकिन कॉलेजों में इन्हें लागू न करके सौतेला व्यवहार अपनाया जा रहा है।

मान्यवर, हमारी आपसे विनम्र विनती है कि उपरोक्त तीनों समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए अधिकारियों को शीघ्र निर्देश दिए जाएं तथा इनकी अनुपालना की रिपोर्ट मांगी जाए। हमारा विनम्र निवेदन है कि आप हमें अपने कीमती समय में से कुछ क्षण मिलने के लिए प्रदान करें ताकि हम और भी स्पष्ट तरीके से अपना पक्ष रख सकें। इसके लिए शिक्षक वर्ग आपका हृदय से आभारी रहेगा।
धन्यवाद सहित।

भवदीय,

डॉ. सुरेन्द्र पाल सिंह सिधु
महासचिव

Copy to:.
1. माननीय शिक्षामन्त्री, हरियाणा सरकार।
2. माननीय वितमन्त्री, हरियाणा सरकार।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, हरियाणा सरकार।
4. महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग, पंचकूला।
5. वितायुक्त, वित विभाग, चण्डीगढ़।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।

UGC REGULATIONS
ON MINIMUM QUALIFICATIONS
FOR APPOINTMENT OF TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF IN UNIVERSITIES AND COLLEGES AND MEASURES FOR THE MAINTENANCE OF STANDARDS IN HIGHER EDUCATION
2010

To be published in the Gazette of India
Part III Sector 4

University Grants Commission
Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi-110002.

No.F.3-1/2009 28 June, 2010

In exercise of the powers conferred under clause (e) and (g) of sub-section (1) of Section 26 of University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in pursuance of the MHRD O.M.No.F.23-7/2008-IFD dated 23rd October, 2008, read with Ministry of Finance (Department of Expenditure) O.M.No.F.1-1/2008-IC dated 30th August, 2008, and in terms of the MHRD Notification No.1-32/2006-U.II/U.I(1) issued on 31st December, 2008 and in supersession of the University Grants Commission (minimum qualifications required for the appointment and career advancement of teachers in Universities and Institutions affiliated to it) Regulations, 2000, issued by University Grants Commission *vide* Regulation No. F.3-1/2000 (PS) dated 4th April, 2000, together with all amendments made therein from time to time, the University Grants Commission hereby frames the following Regulations, namely:-

1. **Short title, application and commencement:**

1.1. These Regulations may be called the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2010.

1.2. They shall apply to every university established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or a State Act, every institution including a constituent or an affiliated college recognized by the Commission, in consultation with the university concerned under Clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and every institution deemed to be a university under Section 3 of the said Act.

1.3 They shall come into force with immediate effect.

Provided that in the event, any candidate becomes eligible for promotion under Career Advancement Scheme in terms of these Regulations on or after 31st December, 2008, the promotion of such a candidate shall be governed by the provisions of these Regulations.

Provided further that notwithstanding anything contained in these Regulations, in the event any candidate became eligible for promotion under Career Advancement Scheme

Branch Email Id:- hechry1college@gmail.com

पंजीकृत
तुरन्त

प्रेषक

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पंचकूला।

सेवा में,

चेयरमैन,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली–110002

यादी क्रमांक 24/242–2013 सी–1 (4)
दिनांक, पंचकूला। 12/6/15

विषयः– एम0फिल0/पीएच0डी0 की एवज़ में अग्रिम वेतनवृद्धि मूल वेतन में विलय करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में आप द्वारा उप–कुलपति, स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ, नांदेड को जारी पत्र दिनांक 10.6.2013 में यह स्पष्ट नहीं है कि यह पत्र भारत की सभी शिक्षण संस्थाओं पर लागू है या नहीं।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस निदेशालय को सूचित करने का कष्ट करें कि उप–कुलपति, स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ, नांदेड को जारी पत्र दिनांक 10.6.2013 भारत की सभी शिक्षण संस्थाओं पर लागू है या नहीं।

कृप्या इसे परम् अग्रता देने का कष्ट करें।

संलग्नः– पत्र दिनांक 10.6.2013

उप–निदेशक कैडेट कोर
कृतेः निदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला

S.No. 36 (1)

13/-

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
University Grants Commission
Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi – 110002

SPEED POST

No.F.9-3/2010 (PS) Part file.

November, 2017

- 7 NOV 2017

The Chief Accounts Officer (PR),
For Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana,
Finance Department,
33-36, Sector- 4,
Panchkula Haryana – 134 112.

Subject: Grant of non compounded increments on acquiring M.Phil./Ph.D. Degree – reg.

Sir,

With reference to your letter No. 1/46/2009-4PR (FD) dated 20th August, 2017 on the subject mentioned above, I am directed to inform that the NET is not linked with the incentives of Ph.D. at entry level or otherwise.

Yours faithfully

(Ritu Oberoi)
Under Secretary

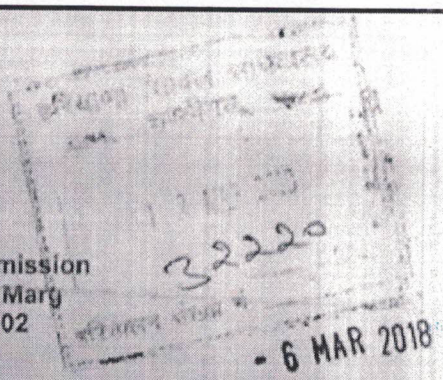

-2-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi – 110002
Speed-Post

SP
0207

32220

- 6 MAR 2018

No.F.9-3/2010(PS)Pt.Fl. March, 2018

The Additional Chief Secretary, (PR),
Government of Haryana,
Finance Department,
Haryana Civil Secretariat,
Chandigarh 160 001.

7920
12/3/18

- 6 MAR 2018

Subject: Grant of non-compounded increments on acquiring M.Phil/Ph.D. Degree - reg.

Sir,

CFMU

FD II

With reference to your letter dated 8/1/2018 and in continuation to this office letter of even number dated 7th March, 2017 on the subject cited above; I am directed to inform you that the non-compounded increments for M.Phil./Ph.D. are not linked with the exemption from NET. These are admissible to the teachers who have been appointed on the basis of Ph.D. and not having NET. But the benefit of these non compounded incentives has to be given only to those teachers who have acquired their Ph.D. strictly in accordance of the UGC M.Phil/Ph.D. Regulation (Minimum Standards and Procedure for the award of M.Phil/Ph.D. Degrees) 2009.

Yours faithfully

(Satish Kumar)
Under Secretary

University Grants Commission
Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi – 110002

No.F.11-6/2011(PS)

August 2015

18 Aug 2015

The Deptt of Higher Education
Shiksha Sadan
Panchkula,
Haryana

Subject : Grant of Non-compounded increments on acquiring M.Phil/Ph.D Degree – reg.

Sir,

With reference to your letter No.24/242-2013 C-1(4) dated 18.6.2015 on the subject cited above, I am directed to enclose a copy of UGC circular No. F.1-2/2009 (EC/PS) Pt.VII dated dated 10th June 2013 which was circulated to All Universities and All Education Secretaries. It is applicable to all Universities.

Yours faithfully

(Satish Kumar)
Under Secretary

ISSUED
876
18/8

Stage 3), provided they are assessed to fulfill the eligibility and performance criteria as laid out in Clause 6.3. of this Regulation.

4.2. An entry level Assistant Professor, possessing Ph. D. Degree in the relevant discipline shall be eligible, for moving to the next higher grade (stage 2) after completion of four years service as Assistant Professor.

4.3. An entry level Assistant Professor possessing M.Phil. Degree or post-graduate Degree in professional courses, approved by the relevant statutory body, such as LL.M. / M. Tech., etc. shall be eligible for the next higher grade (stage 2) after completion of five years service as Assistant Professor.

4.4. An entry level Assistant Professor who does not have Ph.D. or M.Phil, or a Master's Degree in the relevant professional course, shall be eligible for the next higher grade (stage 2) only after completion of six years service as Assistant Professor.

4.5. The upward movement from the entry level grade (stage 1) to the next higher grade (stage 2) for all Assistant Professors shall be subject to their satisfying the API based PBAS conditions laid down by the UGC in this Regulation.

4.6. Assistant Professors who have completed five years of service in the second grade (stage 2) shall be eligible, subject to meeting the API based PBAS requirements laid down by these Regulations, to move up to next higher grade (stage 3).

4.7. Assistant Professors completing three years of teaching in third grade (stage 3) shall be eligible, subject to the qualifying conditions and the API based PBAS requirements prescribed by these Regulations, to move to the next higher grade (stage 4) and to be designated as Associate Professor.

4.8. Associate Professor completing three years of service in stage 4 and possessing a Ph.D. Degree in the relevant discipline shall be eligible to be appointed and designated as Professor and be placed in the next higher grade (stage 5), subject to (a) satisfying the required credit points as per API based PBAS methodology provided in Table I-II of Appendix IV stipulated in these Regulations, and (b) an assessment by a duly constituted selection committee as suggested for the direct recruitment of Professor. *Provided* that no teacher, other than those with a Ph.D., shall be promoted or appointed as Professor.

4.9. In the case of Associate Professors in Colleges, promotion to the post of Professor under CAS shall be further subject to Clause 6.5.1.and 6.5.2 of these Regulations.

4.10. Ten percent of the positions of Professors in a university, with a minimum of ten years of teaching and research experience as professor either in the pre-revised scale of Professor's pay or the revised scale pay will be eligible for promotion to the higher grade of Professorship (stage 6), on satisfying the required API score as per Tables I